



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 10, 2003 (वैशाख 20, 1925)
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 10, 2003 (VAISAKHA 20, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय

मुंबई-400 005, दिनांक 07 मार्च 2003

सं. डीएनबीएस. 01/सीजीएम (सी एस एम)-2003--भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि इसके साथ अनुबंध में दिया गया फॉर्म, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्राप्त करने की इच्छुक प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन का फॉर्म होगा।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्राप्त करने की इच्छुक प्रतिभूतिकरण कंपनियां या पुनर्निर्माण कंपनियां, सभी संगत अनुबंधों/समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ विधिवत् भरा हुआ अपना आवेदनपत्र प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्र-1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005 को प्रस्तुत करेंगी।

सी. एस. मूर्ति
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का कारोबार आरंभ करने /

चलाने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन का फार्म

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अनुसार)

पावती सहित पंजीकृत डाक /हस्त वितरण

कंपनी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

पंजीकृत कार्यालय का पता

सेवा में

प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग,

भारतीय रिजर्व बैंक,

केंद्रीय कार्यालय,

केन्द्र 1, दूसरी मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र,

मुंबई - 400 005

महोदय,

प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का कारोबार आरंभ करने /

जारी रखने* के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

हम एतद्वारा, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हैं। अनुदेशों के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज /सूचना यहां प्रस्तुत हैं।

2. हम प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का कारोबार आरंभ करने /जारी रखने* के इच्छुक हैं। अतः हमारा अनुरोध है कि आप कृपया वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करें ताकि हमारी कंपनी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का कारोबार आरंभ कर सके /जारी रख सके*।

हम सत्य निष्ठापूर्वक यह घोषणा करते हैं कि इस आवेदनपत्र और उसके साथ लगे हुए अनुबंधों तथा संलग्न विवरणों में दी गयी सूचना हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य है। हमें यह ज्ञात है कि यहां पर दी गयी यदि कोई सूचना गलत /अपूर्ण /असत्य पायी जाती है तो पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन रद्द किया जा सकता है और पंजीकरण प्रमाणपत्र यदि मंजूर कर दिया गया हो तो रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

कंपनी की मुहर :

तारीख :

स्थान :

अनुलग्नक : ... पन्ने

- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

अनुबंध-I

कंपनी की पहचान से संबंधित ब्यौरे

भाग-I

1. कंपनी का नाम :
2. निदेशकों की सूची :
3. क्या कंपनी ने पहले कभी अपने नाम में परिवर्तन किया था ? : हां / नहीं
यदि हां, तो पिछले प्रायोजकों के ब्यौरे दें। [कृपया अनुदेशों की मद (10) देखें]
4. क्या कंपनी ने अपने प्रायोजकों को बदला था ? यदि हां, तो :
पिछले प्रायोजकों के ब्यौरे दें।
5. निगमन की तारीख :
6. कारोबार शुरू करने की तारीख :
7. राज्य का नाम, जिसमें कंपनी पंजीकृत है : -----
8. कंपनी का पूरा पता :
(i) पंजीकृत कार्यालय
फोन नं. फैक्स
ई मेल
- (ii) निगमित / प्रशासनिक* कार्यालय
फोन नं. फैक्स
ई मेल
9. हैसियत : (क) सरकारी (ख) निजी :
10. क्या कंपनी : हां / नहीं
(क) 21 जून 2002 को प्रतिभूतिकरण / आस्ति पुनर्निर्माण का कारोबार कर रही है ? यदि हां, तो कब से (ऐसा कारोबार शुरू करने की तारीख)
(ख) गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार सहित कोई अन्य कारोबार। यदि हां, तो कब से (ऐसा कारोबार शुरू करने की तारीख)
11. यदि नियुक्त किये गये हों तो संविधिक लेखा परीक्षकों के नाम :
पता / पते :
फोन नं. / फैक्स :
12. सभी बैंकों के नाम :
पता / पते :
फोन नं. / फैक्स :

13. क्या कंपनी या उससे सम्बद्ध पक्ष (पक्षों) ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित किसी बैंक / किसी अन्य वित्तीय संस्थान से लिए गए किसी ऋण, अग्रिम या किसी अन्य ऋण सुविधा की चुकौती में कोई चूक की है । : हां / नहीं
14. यदि हां, तो पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें, जैसे ऋणदात्री संस्था का नाम तथा शाखा, सुविधा का प्रकार, अवधि अथवा चूक की मात्रा आदि :
15. क्या कंपनी / उससे सम्बद्ध पक्ष ने मोचनीय डिबेंचरों / अधिमान शेयरों / जमा राशियों की चुकौती में कोई चूक की है । : हां / नहीं
16. यदि हां, तो ऐसी चूकों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें :
17. क्या समूह की कोई कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है : हां / नहीं
18. यदि हां, तो क्या उसने पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में आवेदन किया है : हां / नहीं
19. यदि हां, तो क्या उसे पंजीकृत किया गया / रद्द किया गया : हां / नहीं
20. यदि पंजीकृत किया गया हो तो पंजीकरण सं. :
पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख :

भाग-I

अनुबंध-II

..... तक की स्थिति से संबंधित स्वाधिकृत निधि का विवरण
(कृपया अनुदेशों की मद सं. 11 देखें)

(लाख रु. में)

	मद	राशि रुपये में
(i)	चुकता ईक्विटी पूंजी	
(ii)	अनिवार्य रूप से ईक्विटी में परिवर्तित किये जाने की सीमा तक चुकता अधिमान पूंजी	
(iii)	मुक्त आरक्षित निधियां (पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों के अलावा) (क) सामान्य आरक्षित निधियां (ख) शेयर प्रीमियम आरक्षित निधि (ग) पूंजीगत प्रारक्षित निधियां (अलग खाते में रखा हुआ आस्तियों के विक्रय के बाद रोक रखे गये अधिशेष को दर्शाने वाली) (घ) डिबेंचर मोचन निधि (ङ) पूंजी मोचन निधि (च) लाभ-हानि लेखे में जमा शेष	
(iv)	(i) से (iii) का जोड़	
	घटाएं	
(v)	हानि का संचित शेष	
(vi)	आस्थागित राजस्व व्यय	
(vii)	अन्य अगोचर आस्तियां	
(viii)	निवेशों के मूल्य के संबंध में अल्प / कम प्रावधान करना [मद (xi) के अंतर्गत आने वाले निवेशों के अलावा]	
(ix)	अनर्जक आस्तियों / अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए अल्प / कम प्रावधान करना [मद (xi) के अंतर्गत आने वाले निवेशों के अलावा]	
(x)	आय का अति निर्धारण	
(xi)	प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी में अर्जित शेयरों का बही मूल्य	
(xii)	लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों से संबंधित अपनी रिपोर्ट में निर्दिष्ट मदों के कारण अपेक्षित अन्य सभी कटौतियां	
(xiii)	जोड़ (v से xii तक)	
(xiv)	स्वाधिकृत निधि (iv - xiii)	

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम

पदनाम

कंपनी की मुहर

दिनांक :

स्थान :

* लागू न हो उसे काट दें

भाग-II

प्रायोजक* / प्रायोजकों का शेयर धारिता पैटर्न (कृपया अनुदेशों की मद 9 देखें)

क्र.	प्रायोजक का नाम तथा पता	रखे गये शेयरों की सं.	राशि	कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत	क्या नियंत्रण हित बनाए रखा है
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम :
 परनाम :
 दिनांक :
 स्थान :
 कंपनी की मुहर :

* लागू न हो उसे काट दें

लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

हमने मेसर्स लिमिटेड द्वारा तक की अपनी स्वाधिकृत निधि के संबंध में रखी गयी लेखा बहियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है और हम सूचित करते हैं कि स्वाधिकृत निधि के विवरण में दर्शाये गये आंकड़े हमारे अच्छे ज्ञान तथा हमें दी गयी जानकारी / स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों में दर्शाये अनुसार सही है।

सनदी लेखाकार / सांविधिक लेखा परीक्षक*

दिनांक :

स्थान :

* प्रमाणपत्र पर यदि नियुक्त किये गये हों तो, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।

अनुबंध-III

**कंपनी के अध्यक्ष, प्रबंधक निदेशक, निदेशकों
तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी
के संबंध में सूचना**

1. नाम :
2. पदनाम : अध्यक्ष / प्रबंधक निदेशक /
निदेशक / मुख्य कार्यपालक
अधिकारी*
3. राष्ट्रीयता :
4. आयु :
5. कारोबार का पता :
6. आवास का पता :
7. आय कर पैत्र नं. :
8. शैक्षणिक / व्यावसायिक अर्हताएं :
9. कारोबार / व्यवसाय :
10. अन्य कंपनियों के नाम, जिनमें उक्त व्यक्ति अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य
कार्यपालक अधिकारी के पद पर रहा है । :
11. (i) क्या वह अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी सहित किसी गैर बैंकिंग वित्तीय
कंपनी के साथ प्रायोजक, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष अथवा निदेशक के
रूप में सम्बद्ध है :
- (ii) यदि हां, तो कंपनी / कंपनियों के नाम (यदि आवश्यक हो तो अलग
पत्रक जोड़ा जाये)
12. (i) क्या उस पर या तो वैयक्तिक क्षमता में या किसी फर्म / कंपनी के
साझेदार / निदेशक के रूप में नैतिक भ्रष्टता या किसी आर्थिक अपराध
में शामिल होने के लिए मुकदमा चलाया गया / दोषी पाया गया है । :
- (ii) यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें ।
13. (i) क्या किसी कंपनी में निदेशक होने के लिए भारतीय प्रतिभूति और
विनिमय बोर्ड द्वारा पूर्व में उन पर रोक लगायी गयी है :
- (ii) यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें
14. (i) क्या किसी कंपनी का निदेशक होने के लिए उसे पूर्व में कंपनी अधिनियम,
1956 के अंतर्गत उसे अयोग्य ठहराया गया था :
- (ii) यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें
15. वित्त, प्रतिभूतिकरण तथा आस्ति पुनर्निर्माण के क्षेत्र का अनुभव (ब्योरा) (यदि
आवश्यक हो तो अलग पत्रक जोड़ा जाये)
16. आवेदक कंपनी में इक्विटी शेयर धारिता :
- (i) शेयरों की संख्या
- (ii) अंकित मूल्य
- (iii) कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत
17. क्या किसी प्रायोजक का नामिती या उसके साथ सम्बद्ध है :
18. सभी बैंक ब्यौरे : खाता संख्या, सभी बैंकों के नाम और पते :
19. क्या उसने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित किसी बैंक / किसी अन्य वित्तीय संस्था
से लिये गये ऋण, अग्रिम या किसी अन्य ऋण सुविधा की चुकौती में कोई चूक की है :
20. यदि हां, तो पूरे ब्यौरे, जैसे ऋणदात्री संस्था का नाम तथा शाखा, सुविधा का प्रकार
और चूक की मात्रा आदि, प्रस्तुत करें ।

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण में प्रस्तुत सूचना मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण तथा सत्य है।

सूचना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

दिनांक :

स्थान :

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण में प्रस्तुत सूचना मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण तथा सत्य है।

(कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

दिनांक :

स्थान :

लागू न हो उसे काट दें

अनुबंध IV

कंपनी के प्रायोजक/प्रायोजकों से संबंधित जानकारी

1.	नाम	:	
2	कारोबार का पता	:	
3	आवास का पता	:	
4	आय कर पैन नं.	:	
5	कारोबार / व्यवसाय	:	
6	बैंक खाता सं., बैंकों के नाम तथा पते	:	
7	क्या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित किसी बैंक / किसी अन्य वित्तीय संस्था से लिये गये किसी ऋण, अग्रिम में या किसी अन्य ऋण सुविधा के संबंध में चुकौती में कोई चुक की है।	:	हां/नहीं
8	यदि हां, तो पूरे ब्योरे अर्थात् ऋणदात्री संस्था का नाम तथा शाखा, सुविधा का प्रकार, चुक की अवधि तथा मात्रा आदि, प्रस्तुत करें।	:	
9	क्या कंपनी / सहायक कंपनी / उसी समूह की अन्य कंपनियों ने मोचनयोग्य डिबेंचरों / अधिमान शेयरों / जमा राशियों की चुकौती में कोई चुक की है।	:	हां/नहीं
10	क्या उसके संस्था के बहिर्नियमों तथा संस्था के अंतर्नियमों के उद्देश्य खंड में प्रतिभूतिकरण कंपनी अथवा पुनर्निर्माण कंपनी में निवेश करने की अनुमति दी गयी है।	:	हां/नहीं
11	पुनर्निर्माण कंपनी या प्रतिभूतिकरण कंपनी में निवेश की सीमा	:	
	(i) शेयरों की संख्या	:	
	(ii) अंकित मूल्य	:	
	(iii) कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत	:	
12	क्या प्रायोजक नियंत्रक कंपनी है / या प्रस्तावित कंपनी पर नियंत्रण है	:	

मैं गत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण में प्रस्तुत सूचना मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण तथा सत्य है।

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर :

नाम :

दिनांक :

स्थान :

पदनाम :

कंपनी की मुहर

अनुबंध V

संबंधित पक्षों से संबंधित जानकारी

1. संबंधित पार्टी का नाम
2. पूरा पता :
3. कारोबार :
4. स्थिति : (क) वैयक्तिक फर्म (ख) सरकारी लिमिटेड कंपनी / निजी लिमिटेड कंपनी
5. आवेदक कंपनी के साथ सम्बन्ध :

6. ऋण आदि जोखिम के ब्योरे

मद	राशि (लाख रुपयों में)
पूँजी शेयरों, बांडों / डिबेंचरों में निवेश	
बकाया ऋण तथा अग्रिम	
जमा राशियाँ	
जोड़	

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण में प्रस्तुत सूचना मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण तथा सत्य है।

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर :

नाम

दिनांक :

पदनाम :

स्थान :

कंपनी की मुहर

आवेदन फॉर्म के साथ अनुबंध के रूप में लगाये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

1. कंपनी की पहचान से संबंधित विवरण (अनुबंध I)
2. स्वाधिकृत निधि का विवरण (अनुबंध II)
3. प्रबंधन के बारे में सूचना (अनुबंध III)
4. प्रायोजक/प्रायोजकों के बारे में सूचना (अनुबंध IV)
5. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानकों तथा दिशा-निर्देश नोटों में परिभाषित अनुसार संबंधित पार्टियों से संबंधित सूचना
6. कंपनी के बहिर्नियमों तथा अंतर्नियमों की अद्यतन प्रमाणित प्रतिलिपि (जिसमें इस आशय का प्रमाण दिया हो कि कंपनी केवल प्रतिभूतिकरण / आस्ति पुनर्निर्माण कारोबार के प्रयोजन के लिए बनायी गयी है)।
7. निगमन प्रमाणपत्र तथा कारोबार शुरू करने के प्रमाणपत्र (यदि सरकारी लिमिटेड कंपनियां हो तो) में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. निदेशक मंडल के प्रत्येक संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि, जिसमें (i) विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन और उसकी विषय-वस्तु तथा प्राधिकृत अधिकारियों के नामों का अनुमोदन किया गया हो (ii) यह कहा गया हो कि कंपनी ने कोई जमाराशि (भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ (ख ख) में परिभाषित अनुसार) स्वीकार नहीं की है / स्वीकार की गयी जमाराशि की संविदा के अनुसार चुकौती की जायेगी तथा कंपनी ने अभी तक जमाराशियों / उन पर ब्याज की चुकौती में चूक नहीं की है, (iii) यह कहा गया हो कि कंपनी के निदेशकों को वित्त, प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण से संबंधित मामलों का पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव है अथवा नहीं (iv) यह कहा गया हो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किये जाने वाले निदेशकों में से कोई भी निदेशक अपात्र नहीं है और (v) यह कहा गया हो कि कंपनी यदि आवेदन की तारीख को या उससे पहले, अधिनियम में परिभाषित अनुसार प्रतिभूतिकरण / आस्ति पुनर्निर्माण के कारोबार के अलावा कोई अन्य कारोबार कर रही थी और उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण मंजूर कर दिया जाता है तो वह 20 जून 2003 तक वह कारोबार बंद कर देगी (प्रतिभूतिकरण का वह कारोबार करना, जो उक्त अधिनियम की धारा 2(1) य क में प्रतिभूतिकरण की परिभाषा में नहीं आता है, तो वह 'अन्य कार्यकलाप' में आयेगा)
9. निदेशक मंडल के इस आशय के संकल्प की प्रमाणित प्रति तथा लेखा परीक्षक का मूल प्रमाणपत्र कि :
 - (i) कंपनी ने पूर्ववर्ती तीन वर्षों में से किसी वित्तीय वर्ष में हानियां नहीं उठायी है; (केवल वर्तमान कंपनियों के लिए)
 - (ii) कंपनी ने प्रतिभूतिकरण तथा आस्ति पुनर्निर्माण के अलावा कोई अन्य कारोबार नहीं किया है / नहीं करेगी (केवल वर्तमान कंपनियों के लिए),
 - (iii) प्रायोजकों में से कोई प्रायोजक किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी की नियंत्रक कंपनी नहीं है या इसके ऐसी किसी अन्य प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी पर अन्य प्रकार से उसका नियंत्रण नहीं है;
 - (iv) कंपनी के निदेशक मंडल में उसके निदेशकों की कुल संख्या के, जो या तो किसी प्रायोजक के नामित हैं, या प्रायोजक के साथ अथवा अपनी किसी सहयोगी संस्था से सम्बद्ध हैं, आधे से अधिक निदेशक नहीं होने चाहिए;
10. निदेशक मंडल को रिपोर्ट द्वारा यह स्पष्ट करना होगा कि कंपनी ने प्रतिभूतिकरण / आस्ति पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु अर्जित वित्तीय आस्तियों की वसूली के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं और कंपनी विनिर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं या अन्य व्यक्तियों को संबंधित नियत तारीखों को अपनी वचनबद्धताएं पूरी करेगी।
11. लाभ और हानि लेखे तथा लेखा परीक्षित तुलनपत्र की एक प्रति पिछले 3 वर्षों अथवा उपलब्ध लघुतर अवधि के वर्तमान कंपनियों के लिए)।
12. निम्नलिखित के संबंध में ब्योरा देते हुए कंपनी के कारोबार की योजना :
 - (क) कारोबार का उद्देश्य;
 - (ख) अधिगृहीत की जाने वाली वित्तीय आस्तियों की प्रस्तावित राशि;
 - (ग) बाजार खंड;
 - (घ) निवेश तथा आय का प्रक्षेपण;
 - (ङ) वित्तीय आस्तियों तथा देयताओं का विवरण; और
 - (च) संगठनात्मक ढांचा

* जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुदेश**(आवेदनपत्र का फॉर्म इन अनुदेशों के अनुसार विधिवत भरा हुआ होना चाहिए)****सामान्य**

1. आवेदन केवल इसी फॉर्म में किया जाना चाहिए। जहां कहीं जगह अपर्याप्त हो, अलग पत्र/पत्रकों में सूचना प्रस्तुत की जाये।
2. विधिवत भरे गये आवेदन पत्र, अनुलग्नकों सहित गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, केंद्र -I, दूसरी मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र, मुंबई - 400 005 को 20 मार्च 2003 को या उससे पहले दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।
3. अनुलग्नकों/अनुबंधों सहित प्रस्तुत आवेदन की फोटोप्रति कंपनी के पास उसके रिकार्ड के लिए रखी जाये।
4. आवेदन पत्र निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए (अर्थात् अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ कंपनी सचिव, जिन्हें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है)।
5. आवेदन पर कंपनी की मुहर लगी होनी चाहिए।
6. आवेदन प्रस्तुत करने पर भारतीय रिजर्व बैंक से पावती प्राप्त की जाये।
7. अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख के अनुसार स्वाधिकृत निधि का विवरण।

अनुबंध I

8. 'प्रायोजक' वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में यथा परिभाषित।
9. "नियंत्रण" में बहुमत निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार या अपनी शेयर धारित या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करारों या मतदान करारों या किसी अन्य प्रकार से किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधन पर नियंत्रण रखना या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीतिगत निर्णय लेना शामिल हैं।
10. यदि कंपनी ने अपने नाम में पहले परिवर्तन किया हो, तो कंपनी के पिछले सभी नामों और परिवर्तन की तारीखों की सूची और नाम में परिवर्तन करने के समय में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम प्रस्तुत करें।

अनुबंध II

11. आवेदन के अनुबंध II में प्रस्तुत किये जाने वाले व्योरे/सूचना अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र में प्रकट किये गये अनुसार आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। तथापि, 21.6.2002 को या उसके पश्चात् निर्गमित कंपनी से संबंधित व्योरे/सूचना आवेदन की तारीख से अधिकतम 30 दिन पहले आने वाली तारीख के तुलन पत्र पर आधारित होनी चाहिए।
12. 'मुक्त आरक्षित निधि' में, तुलन पत्र में दर्शायी गयी तथा लाभों में से आबंटन से सृजित आरक्षित निधियां शामिल हैं परंतु उसमें (क) किसी भावी देयता की चुकौती के

लिए या आस्तियों के मूल्यहास के लिए या अशोध्य ऋणों हेतु निर्माण की गयी आरक्षित राशियां या (ख) कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यन से सृजित आरक्षित राशियां शामिल नहीं होनी चाहिए।

13. 'सम्बद्ध पक्ष' का आशय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों तथा मार्गदर्शी नोटों के अनुसार सम्बद्ध पक्षों से है।
14. अनर्जक आस्तियों के लिए निवेशों के मूल्य में अल्प / कम प्रावधान करना और आय का अति निर्धारण सांविधिक लेखा-परीक्षकों/आंतरिक लेखा परीक्षकों/ रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी द्वारा अभिनिर्धारित किये गये अनुसार होगा।
15. अनुबंध II की विषय-वस्तु सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

अनुबंध III

16. कंपनी के प्रायोजक, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशकों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित सूचना कंपनी के प्रत्येक व्यक्ति, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशकों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा आवेदक कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
17. इस फॉर्मेट में ऐसे प्रत्येक कार्यकर्ताओं का अलग फॉर्म प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुबंध IV

18. प्रायोजकों में से प्रत्येक के संबंध में अलग फॉर्म प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुबंध V

19. प्रत्येक संबंधित पार्टी के संबंध में अलग फॉर्म प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
 20. अनुबंध II में दिये गये अनुसार विवरण/सूचना पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र की तारीख के आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए।
-

भारतीय रिजर्व बैंक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
विश्व व्यापार केंद्र, केंद्र-1
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई

सं. गैबैपवि 2 / सीजीएम (सीएसएम)-2003 दिनांक : 23 अप्रैल 2003

प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश और निदेश, 2003

भारतीय रिजर्व बैंक, जनहित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित के लिए विनियमित करने के हेतु रिजर्व बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ और किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के निवेशकों के हित के लिए हानिकारक ढंग से चलाये जा रहे, कार्यलापों या ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के हित में किसी भी प्रकार से पक्षपाती ढंग से चलाये जा रहे कार्यकलापों को रोकने के लिए; पंजीकरण, आस्ति पुनर्निर्माण के उपायों, कंपनी के कार्यों, विवेकसम्मत मानदंडों, वित्तीय आस्तियों के अभिग्रहण और उससे संबंधित यहां नीचे उल्लिखित उससे संबंधित मामलों से संबंधित दिशानिर्देश तथा निदेश जारी करना आवश्यक है, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3, 9, 10 तथा 12 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा प्रत्येक प्रतिभूतिकरण / कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को, यहां इसके बाद विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देश तथा निर्देश जारी करता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) ये दिशा-निर्देश और निदेश 'प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश तथा निदेश, 2003' के नाम से जाने जायेंगे।
- (2) ये 23 अप्रैल 2003 से लागू होंगे और इन दिशा-निदेशों तथा निदेशों में इनके लागू होने की तारीख का कोई संदर्भ उक्त तारीख का संदर्भ माना जायेगा।

निदेशों की प्रयोजनशीलता

2. इन दिशा-निर्देशों तथा निदेशों के प्रावधान, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों पर लागू होंगे। परंतु यहां पैराग्राफ 8 में उल्लिखित न्यास/न्यासों के संबंध में, पैराग्राफ 4,5,6,9,10(i), 10 (iii), 12, 13, 14 और 15 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

3. परिभाषाएँ

- (1) (i) "अधिनियम" का अर्थ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 है ।
- (ii) "बैंक" का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अंतर्गत गठित रिज़र्व बैंक है ;
- (iii) "अभिग्रहण की तारीख" का अर्थ उस तारीख से है, जब प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा वित्तीय आस्तियों का स्वामित्व ग्रहण किया गया है ;
- (iv) "जमाराशि" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 क के अंतर्गत बनाये गये कंपनी (जमाराशियों का स्वीकरण) नियम, 1975 में यथा परिभाषित जमाराशि से है ;
- (v) "उचित मूल्य" का अर्थ अर्जन मूल्य (अर्निंग वैल्यू) तथा अलग-अलग (ब्रेक-अप) मूल्य के माध्य से है ;
- (vi) "अनर्जक आस्ति" (एनपीए) का अर्थ किसी आस्ति से है, जिसके संबंध में :
- (क) ब्याज या मूलधन (या उसकी किश्त), ऋण या अग्रिम प्राप्त करने की तारीख अथवा उधार लेने वाले और प्रवर्तक (ऑरीजिनेटर) के बीच संविदा के अनुसार नियत तारीख से, जो भी बाद में हो 180 दिन या उससे अधिक दिन के लिए अतिदेय हो ;
- (ख) ब्याज या मूलधन (या उसकी किश्त), यहां पैराग्राफ 7(1)(6) में उल्लिखित आस्तियों की वसूली के लिए बनायी गयी योजना में, उसकी प्राप्ति के लिए नियत तारीख से 180 दिन या उससे अधिक दिन की अवधि के लिए अतिदेय हो ;
- (ग) ब्याज या मूलधन (या उसकी किश्त), यहां पैराग्राफ 7(1)(6) में उल्लिखित आस्तियों की वसूली के लिए जब कोई योजना नहीं तैयार की गयी हो तो योजना अवधि की समाप्ति पर अतिदेय होती है ; या
- (घ) कोई अन्य प्राप्य राशि, यदि वह प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी की बहियों में 180 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो ।
- परंतु शर्त यह है कि किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का निदेशक मंडल उधारकर्ता द्वारा चूक करने पर किसी आस्ति को ऊपर उल्लिखित अवधि से पहले भी अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर सकता है (उक्त अधिनियम की धारा 13 में किये गये उपबंध के अनुसार प्रवर्तन में सुविधा के लिए) ।
- (vii) "अतिदेय" का अर्थ किसी उस राशि से है, जो नियत तारीख के बाद अप्रदत्त (अनपेड) रहती है ।

- (viii) "स्वाधिकृत निधि" का अर्थ चुकता ईक्विटी पूंजी, अनिवार्य रूप से ईक्विटी पूंजी में परिवर्तनीय सीमा तक चुकता अधिमान पूंजी, मुक्त आरक्षित निधि (पुनर्मूल्य आरक्षित निधि को छोड़कर) लाभ और हानि खाते में नामे शेष तथा विविध खर्चे (बट्टा खाते में न डाली गई या समायोजित न की गई सीमा तक), अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य और अनर्जक आस्तियों के लिए अल्प / कम प्रावधान / निवेशों के मूल्य में हास तथा अधिक आय निर्धारण को, यदि कोई किया गया हो तो, घटाकर तथा आगे किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के अर्जित शेषों का बही मूल्य और वित्तीय विवरणों के संबंध में लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में नियत किये गये मुद्दों के लिए अपेक्षित अन्य कटौतियों को घटाने के बाद लाभ और हानि खाते में जमाशेष के कुल योग से है ;
- (ix) "योजना अवधि" का अर्थ पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु अर्जित की गयी अनर्जक आस्तियों (प्रवर्तक की बहियों में) की वसूली हेतु योजना बनाने के लिए अनुमति प्रदान की गई अधिकतम 12 महीने की अवधि से है ;
- (x) "मानक आस्ति" का अर्थ किसी ऐसी आस्ति से है, जो अनर्जक आस्ति नहीं है ।
- (xi) "न्यास" का अर्थ भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 3 में यथापरिभाषित न्यास से है ।
- (2) यहां पर प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनकी यहां परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में जिनकी परिभाषा दी गई है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अधिनियम में उनका अर्थ है । अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनकी परिभाषा उक्त अधिनियम में नहीं दी गई है, अर्थ वह होगा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 में उनका अर्थ है ।

4. पंजीकरण और उससे संबंधित मामले

- (i) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी, 7 मार्च 2003 की अधिसूचना सं.गैबैवि.1 / सीजीएम (सीएसएम) 2003 में विनिर्दिष्ट आवेदन फॉर्म में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगी और उक्त अधिनियम की धारा 3 में किये गये उपबंध के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी;
- (ii) कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी, जिसने उक्त अधिनियम के अंतर्गत बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण दोनों कार्यकलाप कर सकती है ;
- (iii) कोई संस्था जो, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बैंक में पंजीकृत नहीं है, अधिनियम के दायरे के बाहर प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्निर्माण का कारोबार कर सकती है ।

5. स्वाधिकृत निधि

प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को, जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बैंक में पंजीकरण की इच्छुक है, न्यूनतम 2 करोड़ रुपये की स्वाधिकृत निधि रखनी होगी।

6. स्वीकार्य कारोबार

- (i) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी केवल प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्निर्माण के कार्यकलाप तथा उक्त अधिनियम की धारा 10 में उपबंधित कार्य करेगी।
- (ii) उस प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को, जो कोई अन्य कारोबार कर रही है, 20 जून 2003 तक वह कारोबार बंद कर देगी;
- (iii) कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी जमा के रूप में कोई धन नहीं उगाहेगी।

7. आस्ति पुनर्निर्माण

(1) वित्तीय आस्तियों का अभिग्रहण

- (i) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण कंपनी, पंजीकरण प्रमाण पत्र की मंजूरी के 90 दिन के अंदर अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक 'वित्तीय आस्ति अभिग्रहण नीति' बनाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट रूप से निम्नलिखित के संबंध में नीतियां और दिशा-निर्देश निर्धारित किये जायेंगे :
 - (क) अभिग्रहण के लिए मानदंड और क्रिया विधि;
 - (ख) आस्तियों के प्रकार और वांछित रूप रेखा;
 - (ग) यह सुनिश्चित करते हुए कि अर्जित की गयी आस्तियों का वसूलीयोग्य मूल्य है, जिसका उचित रूप से आकलन और तटस्थ रूप से मूल्यन किया जा सकता है, मूल्यन की क्रिया विधि;
 - (घ) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए अर्जित वित्तीय आस्तियों के मामले में, उनकी वसूली के लिए योजना बनाने हेतु निदेशक मंडल के मापदंड।
- (ii) निदेशक मंडल वित्तीय आस्तियों के अभिग्रहण के प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने के लिए निदेशक और/या कंपनी के किसी अधिकारी को लेकर बनायी गयी किसी समिति को अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकता है।
- (iii) नीति से हट कर कोई निर्णय केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिए।

(2) उधारकर्ता के कारोबार के उल्लंघन में परिवर्तन / उसकी बिक्री या पट्टे पर देना

कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी, जब तक इस संबंध में बैंक द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी नहीं किये जाते, तब तक उक्त अधिनियम की धारा 9 (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट उपाय नहीं करेगी।

(3) ऋणों की पुनर्व्यवस्था करना

- (i) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उधार लेने वालों से प्राप्य ऋणों की पुनर्व्यवस्था करने के लिए स्थूल मापदंड निर्धारित करते हुए निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक नीति बनायेगी;
- (ii) सभी प्रस्ताव उधार लेने वाले के कारोबार की स्वीकार्य योजना, अनुमानित आय और नकदी प्रवाहों के अनुसार तथा उन के द्वारा समर्थित होने चाहिए;
- (iii) प्रस्तावों से प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का आस्ति देयता प्रबंधन अधिक मात्रा में प्रभावित नहीं होना चाहिए।
- (iv) निदेशक मंडल, ऋणों की पुनर्व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए किसी निदेशक और / या कंपनी के किसी अधिकारी को लेकर बनी एक समिति को अधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है।
- (v) नीति से हट कर कोई निर्णय केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिए।

(4) प्रतिभूति हित प्रवर्तन

उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत जमानती आस्तियों की बिक्री की कार्रवाई करते समय, यदि उक्त बिक्री केवल सार्वजनिक नीलामी के रूप में की जा रही हो तो कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उक्त जमानती आस्तियों को या तो अपने उपयोग के लिए या पुनर्बिक्री के लिए अर्जित कर सकती है।

(5) उधार कर्ताओं द्वारा देय राशियों का निपटारा

- (i) उधारकर्ताओं से प्राप्य ऋणों के निपटारे हेतु स्थूल मापदंड निर्धारित करते हुए प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी निदेशक मंडल के विधिवत अनुमोदित से एक नीति बनाएगी;
- (ii) उक्त नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निर्दिष्ट तारीख, वसूली योग्य राशि के अभिकलन और लेखा के निपटारे का सूत्र, भुगतान की शर्तें और नियत की हुई राशि का भुगतान करने की उधारकर्ता की सामर्थ्य जैसे पहलुओं को शामिल किया जा सकता है ;
- (iii) जब उक्त निपटारे में करार सम्मत संपूर्ण राशि के एकमुश्त भुगतान का विचार नहीं किया गया हो तो प्रस्ताव कारोबार की स्वीकार्य योजना

उधारकर्ता की अनुमानित आय और नकदी प्रवाहों के अनुसार तथा उससे समर्थित होने चाहिए ;

- (iv) इन प्रस्तावों से प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का आस्ति देयता प्रबंधन या निवेशकों को दिये गये आश्वासन अधिक प्रभावित नहीं होने चाहिए ;
- (v) निदेशक मंडल, देय राशियों के निपटारे हेतु प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने के लिए किसी निदेशक और / या कंपनी के किसी अधिकारी को लेकर बनी एक समिति को अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकता है ;
- (vi) नीति से हट कर निर्णय केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिए ।

(6) वसूली की योजना

- (i) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को योजना अवधि के अंदर आस्तियों की वसूली के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित एक या अधिक उपाय किये जा सकते हैं;
 - (क) उधारकर्ता द्वारा देय ऋणों के भुगतान की पुनर्व्यवस्था करना;
 - (ख) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति में हित का प्रवर्तन (एनफोर्समेंट)
 - (ग) उधारकर्ता द्वारा देय राशियों का निपटारा
 - (घ) यहां ऊपर पैराग्राफ 7(2) में उल्लिखित अनुसार इस संबंध में बैंक द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश बनाये जाने के बाद उधारकर्ता के कारोबार के संपूर्ण या उसके एक भाग के प्रबंधन में परिवर्तन या अधिग्रहण या विक्री या पट्टे का अधिग्रहण ।

(ii) वसूली की योजना में आस्तियों के पुनर्निर्माण और एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर उनकी वसूली के लिए प्रस्तावित उपायों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ।

8. प्रतिभूतिकरण

(1) प्रतिभूति की रसीदें जारी करना

प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 7(1) और (2) के उपबंधों को, विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए स्थापित किए गये एक या अधिक न्यासों के माध्यम से लागू करेगी । प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उक्त आस्तियों को उपर्युक्त न्यासों को उसी मूल्य पर हस्तांतरित करेगी, जिस पर वे प्रवर्तक (ऑरीजिनेटर) से अर्जित की गई थीं;

- i. उक्त न्यास केवल विनिर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं को भी प्रतिभूति की रसीदें जारी करेंगे; और उक्त वित्तीय आस्तियों को इन विनिर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं के लाभ के लिए रखेंगे और उनका प्रबंध करेंगे ।
- ii. इन न्यासों की न्यासधारिता उक्त प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के पास रहेगी;

- iii. प्रतिभूति की रसीदें जारी करने वाली कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उक्त रसीदें जारी करने से पहले उक्त ट्रस्ट द्वारा बनायी गयी प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्रतिभूति की रसीदें जारी करने का प्रावधान करते हुए निदेशक मंडल के विधिवत् अनुमोदन से एक नीति बनायेगी;
- iv. उपर्युक्त उप पैराग्राफ (iii) में संदर्भित नीति में यह प्रावधान किया जायेगा कि जारी की गयी प्रतिभूति की रसीदें केवल अन्य विनिर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं को ही हस्तांतरणीय /समनुदेशन योग्य होंगी ।

(2) प्रकटीकरण

प्रतिभूति की रसीदें जारी करने की इच्छुक प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी अनुबंध में उल्लिखित अनुसार प्रकटीकरण करेगी ।

9. पूंजी पर्याप्तता की अपेक्षा

(1) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी निरंतर आधार पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात कायम रखेगी जो उसकी कुल जोखिम भारित आस्तियों के 15% से कम नहीं होगा । जोखिम भारित आस्तियों की गणना तुलनपत्र की और तुलनपत्र बाह्य मदों के सकल भार के रूप में यहां नीचे दिये ब्यौरे के अनुसार की जायेगी :

भारित जोखिम आस्तियां

तुलनपत्र की मदें

जोखिम भार का प्रतिशत

(क) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में नकदी और जमाराशि	0
(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	0
(ग) अन्य आस्तियां	100
तुलनपत्र बाह्य मदें	
सभी आकस्मिक देयताएं	50

(2) अन्य प्रतिभूतिकरण कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों के धारित शेयरों पर कोई जोखिम भार नहीं होगा ।

10. निधियों का अभिनियोजन

- i. कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी प्रवर्तक के रूप में और कोई संयुक्त उद्यम स्थापित करने के प्रयोजनार्थ आस्ति पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु बनायी गयी किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में निवेश कर सकती है;

- ii. कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी अपने पास उपलब्ध अधिक धनराशिया इस संबंध में उसके निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गयी नीति के अनुसार केवल सरकारी प्रतिभूतियों और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में जमाराशियों में रख सकती है;
- iii. कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी अपनी स्वाधिकृत निधि में से भूमि या भवन में निवेश नहीं करेगी परंतु शर्त यह है कि यह प्रतिबंध उधार ली गयी निधियों और न्यूनतम निर्धारित स्वाधिकृत निधि से अधिक निधियों पर लागू नहीं होगा।

11. लेखा वर्ष

प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार अपना तुलनपत्र और हानि-लाभ खाता तैयार करेगी।

12. आस्ति वर्गीकरण

(1) वर्गीकरण

(i) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी सुपरिभाषित ऋण कमजोरियों की मात्रा और वसूली के लिए प्रासंगिक जमानत पर निर्भर रहने की सीमा को ध्यान में रखते हुए आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी, अर्थात् :

- (क) मानक आस्तियां
- (ख) अनर्जक आस्तियां

(ii) अनर्जक आस्तियों को आगे निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा

(क) 'उप-मानक आस्ति' उसके अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किये जाने की तारीख से अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए

(ख) 'संदिग्ध आस्ति' यदि आस्ति 12 महीने से अधिक अवधि के लिए उप मानक आस्ति रहती है;

(ग) 'हानि आस्ति' यदि उक्त आस्ति 36 महीने से अधिक अवधि के लिए अनर्जक रहती है या उक्त आस्ति या तो प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने के कारण या प्रतिभूति के उपलब्ध न होने के कारण उसकी वसूली न होने के वास्तविक खतरे से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है या उसे प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी या उसके आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षक द्वारा हानि आस्ति के रूप में पहचाना गया है।

(ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा आस्ति पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु अर्जित की गयी आस्तियों को योजना अवधि के दौरान, यदि कोई हो, तो मानक आस्तियों के रूप में माना जा सकता है।

(2) आस्ति पुनर्निर्माण : पुनः सौदाकृत /पुनर्व्यवस्थित आस्तियां

- (i) जब किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा मानक आस्ति से संबंधित ब्याज और /या मूलधन के संबंध में करार की शर्तों का फिर से सौदा किया गया हो या उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया गया हो (योजना अवधि के दौरान से अलग) तो संबंधित आस्ति को फिर से सौदा किये जाने /पुनर्व्यवस्थित किये जाने की तारीख से उप मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा या जैसी भी स्थिति हो उसे संदिग्ध आस्ति के रूप में बने रहने दिया जायेगा ।
- (ii) उक्त आस्ति को पुनः सौदा की हुई /पुनर्व्यवस्थित शर्तों के अनुसार 12 महीने की अवधि के लिए संतोषजनक कार्यनिष्पादन के बाद ही मानक आस्ति के रूप में उन्नत किया जा सकता है ।

(3) प्रावधानीकरण की अपेक्षाएं

प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी अनर्जक आस्तियों के लिए निम्नलिखित अनुसार प्रावधान करेगी :

आस्ति की श्रेणी	अपेक्षित प्रावधान
उप मानक आस्तियां	बकाया राशि के 10% का सामान्य प्रावधान
संदिग्ध आस्तियां	(i) उस सीमा तक 100% प्रावधान जिसके लिए आस्ति, प्रतिभूति के प्राक्कलित वसूलीयोग्य मूल्य में नहीं आती है
	(ii) उपर्युक्त मद (i) के अलावा, शेष बकाया राशि का 50%
हानि आस्तियां	संपूर्ण आस्ति को बट्टे खाते में डाला जायेगा । (यदि किसी कारण से उक्त आस्ति को बहियों में रखा जाता है तो उसके लिए 100% का प्रावधान किया जायेगा)

13. निवेश

सभी निवेशों का मूल्यन, लागत या वसूलीयोग्य मूल्य में से जो भी कम हो उसपर किया जायेगा । जहां पर बाजार की दरें उपलब्ध हों वहां बाजार मूल्य को वसूलीयोग्य मूल्य माना जायेगा और ऐसी स्थिति में जब बाजार की दरें उपलब्ध नहीं हो तो वसूलीयोग्य मूल्य उचित मूल्य (फेयर वेल्यू) होगा । परंतु अन्य पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी में निवेशों को दीर्घकालिन निवेश माना जायेगा और उनका मूल्यन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानकों और दिशा-निर्देश नोटों के अनुसार किया जायेगा ।

14. आय-निर्धारण

- (i) आय-निर्धारण मान्यताप्राप्त लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित होगा।
- (ii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये सभी लेखा मानकों और दिशा-निर्देश नोटों का, वहां तक पालन किया जायेगा, जहां तक वे यहां निहित इन दिशा-निर्देशों और निदेशों से असंगत नहीं हों;
- (iii) सभी अनर्जक आस्तियों के संबंध में ब्याज और किसी अन्य प्रभार का तभी निर्धारण किया जायेगा जब वे वास्तव में वसूल हो गये हों। किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा आस्ति के अनर्जक होनेसे पहले वसूल न की गयी निर्धारित की गयी और अप्राप्त रह रही ऐसी आय को अनिर्धारित कर दिया जायेगा।

15. तुलनपत्र में प्रकटीकरण

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI की अपेक्षाओं के अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी निम्नलिखित अनुसूचियां तैयार करेगी और उन्हें अपने-अपने तुलनपत्र के साथ अनुबंध के रूप में लगायेगी :
 - (i) उन बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के नाम और पते जिनसे वित्तीय आस्तियां अर्जित की गयी हैं और वह मूल्य जिसपर ऐसी आस्तियां प्रत्येक ऐसे बैंक /वित्तीय संस्था से अर्जित किये गये थे;
 - (ii) विभिन्न वित्तीय आस्तियों का उद्योगवार और प्रवर्तकवार फैलाव (फैलाव कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में इंगित किया जाना है);
 - (iii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानकों और दिशा-निर्देश नोटों के अनुसार संबंधित पक्षों का ब्यौरा और उनको देय और उनसे प्राप्य राशियां; और
 - (iv) चार्ट में स्पष्ट रूप से मानक से अनर्जक के रूप में वित्तीय आस्तियों के अंतरण को दर्शाते हुए एक विवरण।
- (2) (i) वित्तीय विवरणों के तैयार करने और उनके प्रस्तुत करने में अपनायी गयी लेखांकन की नीतियां बैंक द्वारा निर्धारित किये गये लागू विवेकसम्मत मानदंडों के अनुरूप होंगी।
 - (ii) जहां पर उक्त लेखांकन नीतियों में से कोई नीति इन निदेशों के अनुरूप नहीं है तो इन निदेशों से हटने के विवरणों का उसके कारणों सहित और उनके कारण होने वाले वित्तीय प्रभाव का ब्यौरा दिया जायेगा। जब ऐसा कोई प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता हो तो उसके कारणों का उल्लेख करते हुए यह तथ्य उस रूप में प्रकट किया जाना चाहिए।

- (iii) तुलनपत्र या लाभ और हानि लेखे में किसी मद के अनुचित व्यवहार को न तो प्रयोग में लायी गयी लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से और न तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखे में नोटों में प्रकटीकरण से परिशोधित हो गया माना जा सकता है।

16. आंतरिक लेखा परीक्षा

प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा उक्त कंपनी द्वारा अपनायी गयी आस्ति अभिग्रहण क्रियाविधियों और आस्ति पुनर्निर्माण के उपायों तथा उससे संबंधित मामलों की आवधिक रूप से जांच और समीक्षा के लिए प्रावधान करते हुए एक कारगर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जायेगी।

17. छूट

बैंक, यदि वह यह मानता है कि प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को किसी परेशानी से बचाने के लिए अथवा किसी उचित और पर्याप्त कारण के लिए, सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों या किसी विशेष प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी या प्रतिभूतिकरण कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों के किसी वर्ग को, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह लगाना चाहे या तो सामान्य रूप से या किसी विशेष अवधि के लिए इन दिशा-निर्देशों और निदेशों के सभी अथवा किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकता है।

सी. एस. मूर्ति
(सी. एस. मूर्ति)

प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

अनुबंध**(1) प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण**

- क. प्रतिभूति रसीदें जारी करने वाले से संबंधित
- पंजीकृत कार्यालय का नाम, स्थान, निगमन की तारीख, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के कारोबार आरंभ करने की तारीख;
 - प्रवर्तकों, शेयरधारकों के विवरण और प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के निदेशक मंडल में, उनकी योग्यताओं और अनुभव के साथ निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा
 - पिछले तीन वर्षों की अथवा कंपनी का कारोबार आरंभ होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, कंपनी की वित्तीय सूचना का सारांश
 - पिछले तीन वर्षों अथवा कारोबार आरंभ करने की तारीख से, जो भी बाद में हुआ हो, प्रतिभूतिकरण/ आस्ति पुनर्निर्माण के, यदि कोई कार्यकलाप किये गये हों तो उनका ब्यौरा
- घ. प्रस्ताव की शर्तें
- प्रस्ताव के उद्देश्य
 - प्रलेख का विवरण, इस आशय के एक प्रकथन के साथ कि प्रतिभूति की रसीदों का हस्तांतरण निर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं तक ही सीमित है, उसके स्वरूप, मूल्यवर्ग, निर्गम मूल्य आदि से संबंधित ब्यौरे देते हुए;
 - आस्तियों के प्रबंधन के लिए की गयी व्यवस्थाएं और प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा ली जाने वाली प्रबंध शुल्क की सीमा;
 - ब्याज दर /संभावित प्रतिफल;
 - मूलधन /ब्याज के भुगतान की शर्तें, अवधिपूर्णता /मोचन की तारीख;
 - शोधन तथा प्रशासन व्यवस्था;
 - यदि कोई हो, तो साख निर्धारण और उक्त निर्धारण के लिए औचित्य का सारांश;
 - उन आस्तियों का विवरण जिनका प्रतिभूतिकरण किया जाना है;
 - आग्नि समूह का भौगोलिक वितरण;
 - आस्ति समूह की अवशिष्ट अवधिपूर्णता, ब्याज दरें, बकाया मूलधन;
 - अंतर्निहित सुरक्षा का स्वरूप और मूल्य, संभावित नकदी प्रवाह, उनकी मात्रा और समय, साख वृद्धि के उपाय
 - आस्तियों के अभिग्रहण की नीति और अपनायी गयी मूल्यन की प्रकृति
 - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से आस्तियों के अभिग्रहण की शर्तें
 - प्रवर्तकों (ऑफिशियल) के पास कार्यनिष्पादन के अभिलेख का ब्यौरा
 - आस्ति समूह में आस्तियों को बदलने की शर्तें
 - जोखिम फैक्टरों का विवरण, विशेष रूप से भविष्य के नकदी प्रवाहों से संबंधित और उक्त जोखिमों को कम करने के लिए किये गये उपाय
 - चूक होने की स्थिति में आस्ति पुनर्निर्माण उपायों को लागू करने के लिए की गयी व्यवस्थाएं यदि कोई हों
 - न्यासी के कर्तव्य
 - आस्ति पुनर्निर्माण के विशिष्ट उपाय यदि कोई हों, जिनके संबंध में निवेशकों से अनुमोदन लिया जायेगा
 - विवाद निवारण प्रक्रिया

(2) तिमाही आधार पर प्रकटीकरण

- तिमाही के दौरान हुई कोई चूक, पूर्व भुगतान, हानियां
- साख निर्धारण में हुआ परिवर्तन, यदि कोई हो;
- वर्तमान आस्ति समूह में नयी आस्ति आने या आस्तियों की वसूली होने से आस्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन
- वर्तमान और पिछली तिमाही का संग्रहण सारांश
- अर्जन की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना जिससे निर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं पर प्रभाव पड़ता हो।

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर

(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी बैंक)

प्रधान कार्यालय**5, यशवन्त निवास रोड, इन्दौर - 452 003 (म.प्र.)**

इन्दौर, दिनांक : ---28.4.2003

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के उन शेयरधारियों के नाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिन्हें वर्ष 2002-2003 के लिए उनके द्वारा धारित शेयरों पर लाभांश देय हो सकता है, यदि बोर्ड द्वारा घोषित किया जाए, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के शेयरधारियों का रजिस्टर अंतरण के लिए दिनांक 10-06-2003 से 19-06-2003 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेगा।

निदेशक मण्डल के आदेश से,

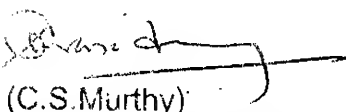
एस. प्रसाद राव
(एस. प्रसाद राव)
प्रबंध निदेशक

**Reserve Bank of India
Department of Non-Banking Supervision
Central Office, Centre No 1
World Trade Centre
Mumbai 400 005**

No.DNBS.1/CGM(CSM)-2003 dated March 7, 2003

The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, hereby, specifies that the form given in the Annexure hereto shall be the form of application to be submitted by the securitisation companies or reconstruction companies seeking registration from the Reserve Bank of India under section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

2. The securitisation companies or reconstruction companies seeking registration from the Reserve Bank of India shall submit their application duly filled in with all the relevant annexures/supporting documents to the Chief General Manager-in-Charge, Department of Non-Banking Supervision, Central Office, Reserve Bank of India, Centre 1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai 400 005.



(C.S. Murthy)
Chief General Manager-in-Charge

Encl : Annexure

**FORM OF APPLICATION FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION TO
COMMENCE / CARRY ON THE BUSINESS OF A SECURITISATION
COMPANY OR RECONSTRUCTION COMPANY**

(Vide Section 3 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

By Registered Post AD/Hand Delivery

Name of the company (in block letters)
Address of registered office

To

The Chief General Manager-in-Charge
Department of Non-Banking Supervision, Second Floor
Reserve Bank of India
Central Office
Centre No 1, World Trade Centre
Mumbai 400 005

Dear Sir,

**Application for a Certificate of Registration to commence / carry on*
the business of a Securitisation Company or Reconstruction Company**

We make this application in terms of sub-section (2) of section 3 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 for issue of a Certificate of Registration. The required documents / information as per the instructions are furnished.

2. We are desirous of commencing / carrying on* the business of a Securitisation Company or Reconstruction Company. Hence, we hereby request you to kindly issue the necessary Certificate of Registration under sub-section (1) of section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002 to enable our company to commence/carry on* the business of Securitisation Company or Reconstruction Company.

We solemnly declare that to the best of our knowledge and belief, the information furnished in this application and the annexures hereto and statements enclosed are correct, complete and true. We are aware that if any of the information furnished herein is found to be incorrect / incomplete / untrue, the application for grant of Certification of Registration is liable to be rejected and the Certificate of Registration, if granted, is liable to be cancelled.

Yours faithfully,

(Signature of Authorised Official)

Name:

Designation:

Company Seal:

Date:

Place:

Encl..... Sheets

*Strike out whichever is not applicable.

Annexure I**IDENTIFICATION PARTICULARS OF THE COMPANY****Part I**

1. Name of the Company :
2. List of Directors :
3. Whether the company had changed its name earlier? : Yes/No
[Please see item (10) of instructions]
4. Whether the company had changed its sponsors? If so, details of earlier sponsors. :
5. Date of incorporation :
6. Date of commencement of business :
7. State in which the company is registered : _____
8. Full Address of the Company
(i) Registered Office
Phone No..... Fax.....
email
(ii) Corporate /Administrative * Office
Phone No..... Fax.....
email.....
9. Status : (a) Public (b) Private
10. Whether the company was transacting : Yes/No
(a) the business of securitisation / asset reconstruction as on June 21, 2002
If yes, since when (date of commencement of such business) :
(b) any other business including the business of an NBFIs. If yes, since when (date of commencement of such business) :

11. Name/s of Statutory Auditor/s, if : _____
appointed : _____
address/es : _____
Phone No./ Fax : _____
12. Name/s of all bankers : _____
address/es : _____
Phone No./ Fax : _____
13. Whether the company or its related : Yes / No
party(s) has/have committed any default
in repayment of any loan, advance or any
other credit facility availed from any bank
/ any other financial institution including
NBFCs.
14. If yes, furnish full details, such as name :
and branch of lending institution , type of
facility, period and quantum of default,
etc.
15. Whether the company / its related party / : Yes/No
has/have committed any default in
repayment of redeemable debentures /
preference shares / deposits
16. If yes, furnish full details of such defaults :
17. Whether any group company is NBFC : Yes/No
18. If yes, whether it has applied for : Yes/No
registration to RBI for grant of a certificate
of registration
19. If yes, whether registered / rejected : Yes/No
20. If registered Registration No. :
Date of issue of :
CoR

Part I**ANNEXURE II****STATEMENT OF OWNED FUND AS ON**

(Please see item No.11 of the instructions)

(Rs. in lakhs)

Item	Amount Rs.
(i) Paid-up Equity Capital	
(ii) Paid up preference capital to the extent compulsorily convertible into equity	
(iii) Free reserves (other than revaluation reserves)	
(a) General Reserves	
(b) Share Premium Reserve	
(c) Capital Reserves (representing retained surplus on sale of assets held in separate account)	
(d) Debentures Redemption Reserve	
(e) Capital Redemption Reserve	
(f) Credit Balance in P&L Account	
(g) Other free reserves (to be specified)	
(iv) Total of (i) to (iii)	
Less	
(v) Accumulated balance of loss	
(vi) Deferred Revenue Expenditure	
(vii) Other Intangible Assets	
(viii) Under / Short provisioning in value of Investments [other than those covered under item (xi)]	
(ix) Under / Short provisioning against NPAs/bad & doubtful debts [other than those covered under Item (xi)]	
(x) Over recognition of income	
(xi) Book value of the shares acquired in Securitisation Company or Reconstruction Company	
(xii) All other deductions required on account of items qualified by the auditors in their report on the financial statements	
(xiii) Total (v to xii)	
(xiv) Owned fund (iv - xiii)	

(Signature of Authorised Official)

Name

Date :

Designation

Place :

Company Seal

* Strike out whichever is not applicable

Part IIShareholding pattern of sponsor/s (Please see item 9 of instructions)

Sr. No.	Name of sponsor & address	No. of shares held	Amount	% to total paid up equity share capital of the Co.	Whether holding controlling interest
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

(Signature of the Authorised Official)

Date :

Place :

Name

Designation

Company Seal

* Strike out whichever is not applicable

AUDITOR'S CERTIFICATE

We have examined the books of account and other records maintained by..... Limited in respect of its owned fund as on and report that to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and as shown by the records examined by us, the figures shown in the statement of owned fund are correct.

Chartered Accountants/Statutory Auditors*

Date :
Place:

*Certificate to be signed by statutory auditors, if appointed.

Annexure III**INFORMATION ABOUT THE CHAIRMAN,
MANAGING DIRECTOR, DIRECTORS AND THE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE COMPANY**

1. Name :
2. Designation / Status : Chairman / Managing Director / Director/Chief Executive Officer*
3. Nationality :
4. Age :
5. Business Address :
6. Residential Address :
7. Income Tax PAN No. :
8. Educational/professional qualifications :
9. Line of business or vocation :
10. Name/s of other companies in which the person has held the post of Chairman/Managing Director/Director/ Chief Executive Officer :
11. (i) Whether associated as Sponsor, Managing Director, Chairman or Director with any NBFC including a Residuary Non-Banking Company. : Yes/No
(ii) If yes, the name/s of the company/ies (Separate sheet may be attached if necessary)
12. (i) Whether prosecuted/convicted for an offence involving moral turpitude or for any economic offence either in the individual capacity or as a partner/director of any firm/company : Yes/No

- (ii) If yes, particulars thereof :
13. (i) Whether barred by SEBI in the past from becoming Director in any company : Yes/No
- (ii) If yes, particulars thereof :
14. (i) Whether disqualified in the past to be director of a company under the Companies Act, 1956 :
- (ii) If yes, particulars thereof :
15. Experience in the field of finance, securitisation and asset reconstruction (details) :
(a separate sheet may be attached, if necessary)
16. Equity shareholding in the applicant company
- (i) No. of shares
- (ii) Face Value
- (iii) Percentage of total paid-up equity share capital of the company
17. Whether nominee of or associated with any of sponsor/s :
18. All Bank details : A/c Nos., all Bankers' names & addresses :
19. Whether committed any default in repayment of any loan, advance or any other credit facility availed from any bank/any other financial institution including NBFCs : Yes/No
20. If yes, furnish full details, such as name and branch of lending institution, type of :

facility, period and quantum of default,
etc.

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information
furnished in the statement above is correct, complete and truly stated.

Signature of the person
furnishing information

Name

Designation

Date :

Place :

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information
furnished in the statement above is correct, complete and truly stated.

(Signature of Authorised Official of the Company)

Name

Designation

Date :

Place :

Company Seal

* Strike out whichever is not applicable.

Annexure IV**INFORMATION ABOUT THE SPONSOR/S OF THE COMPANY**

1. Name :
2. Business Address :
3. Residential Address :
4. Income Tax PAN No. :
5. Line of business or vocation :
6. Bank A/c. No., Banker's name & address :
7. Whether committed any default in repayment of any loan, advance or any other credit facility availed from any bank / any other financial institution including NBFCs. : Yes/No
8. If yes, furnish full details, such as name and branch of lending institution , type of facility, period and quantum of default, etc. :
9. Whether the company / subsidiary / other companies in the same group has/have committed any default in repayment of redeemable debentures / preference shares / deposits : Yes/No
10. Whether object clause in its Memorandum and Articles of Association permits investment in Securitisation Company or Reconstruction Company : Yes/No

11. Extent of investment in Reconstruction Company or Securitisation Company
 - (i) No. of shares
 - (ii) Face Value
 - (iii) Percentage of total paid-up equity share Capital of the company
12. Whether sponsor is holding company / or holding controlling interest in the proposed company :

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information furnished in the statement above is correct, complete and truly stated.

Signature of Authorised official :
Name :

Date : Designation :
Place : Company Seal :

Annexure V

INFORMATION ABOUT RELATED PARTIES

1. Name of related Party :
2. Full Address :
3. Line of business :
4. Status: (a) Individual Firm (b) Public limited company / Private limited Co. :
5. Relationship with applicant company :

6. Details of Exposure

Item	Amount (Rs. in lakh)
Investment in capital shares, bonds/debentures	
Outstanding loans and advances	
Deposits	
Total	

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information furnished in the statement above is correct, complete and truly stated.

Signature of authorised official

Name

Date :

Designation :

Place :

Company Seal :

DOCUMENTS REQUIRED TO BE ANNEXED TO THE APPLICATION FORM

1. Identification particulars of the company (Annexure I).
2. Statement of Owned Fund (Annexure II).
3. Information about the management (Annexure III).
4. Information about the sponsor / s (Annexure IV).
5. Information about related parties as defined in the Accounting Standards and Guidance Notes of ICAI. (Annexure V)
6. Certified copy of up-to-date Memorandum and Articles of Association of the Company (evidencing therein that the company has been formed for the purpose of undertaking securitisation / asset reconstruction business only).
7. A Certified copy each of Certificate of Incorporation and Certificate of Commencement of Business (In case of public Ltd. companies).
8. A certified copy each of the Board of Directors Resolutions (i) specifically approving the submission of the application to Reserve Bank of India and its contents and names of authorised officials; (ii) stating that the company has not accepted any deposit (as defined in Section 45-I(bb) of the Reserve Bank of India Act, 1934)/deposit accepted will be repaid in terms of the contract and the company has not defaulted in repayment of deposits / interest thereon so far, (iii) stating whether or not the directors of the company have adequate professional experience in matters related to finance, securitisation and reconstruction, (iv) stating that none of the directors are disqualified to be appointed as directors as per the provisions of the Companies Act, 1956 and (v) stating that the company, if carrying on any other business other than the business of securitisation/asset reconstruction as defined in the Act on or before the date of application, will cease to carry on any such business by June 20,2003 if the company is granted registration by RBI (carrying out the business of securitisation, which does not fall under the definition of Securitisation as in Section 2(1)za of the Act, will fall under 'other activity').

9. A certified copy of Board of Directors Resolution and Auditor's Certificate (in original) to the effect that;
- (i) the company has not incurred losses in any of the three preceding financial years; (for existing companies only)
 - (ii) the company has not engaged (for existing companies only) / will not engage in any business other than securitisation and asset reconstruction;
 - (iii) any of the sponsors is not a holding company of the securitisation company or reconstruction company, or does not otherwise hold any controlling interest in such securitisation company or reconstruction company,
 - (iv) the Board of Directors of the company does not consist of more than half of its total number of directors who are either nominees of any sponsor or associated in any manner with the sponsor or any of its subsidiaries;
10. The Board of Directors should, by means of a report, state that the company has made adequate arrangements for valuation of the financial assets acquired for the purpose of securitisation / asset reconstruction and that it shall be able to service its obligations on respective due dates to the qualified institutional buyers or other persons.
11. A copy each of the Profit and Loss account and audited Balance Sheet for the last 3 years or for such shorter period as are available (for companies already in existence).
12. Business plan of company for the next three years giving details of its
- (a) thrust of business;
 - (b) amount of Financial Assets proposed to be acquired;
 - (c) market segment;
 - (d) projection of investments and income;
 - (e) statement of Financial Assets and Liabilities; and
 - (f) organisational Structure

*** Delete whichever is not applicable.**

INSTRUCTIONS

(Application form should be filled up strictly in accordance with these Instructions)

GENERAL

1. Application should be made in this form only. Wherever space is insufficient, information may be furnished in separate sheet/s.
2. Application along with enclosures duly completed should be submitted in duplicate on or before March 20, 2003 to the Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India, Central Office, Centre I, 2nd floor, World Trade Centre, Mumbai 400 005.
3. A photocopy of the application together with enclosures / Annexures, as submitted may be kept with the company for its record.
4. Application should be signed by any of the following officials authorised by the Board of Directors in this behalf (viz., Chairman/Managing Director/Director/ Chief Executive Officer/ Company Secretary, hereinafter known as the Authorised Official).
5. Application should bear the company seal.
6. An acknowledgement for having submitted the application may be obtained from the RBI.
7. Statement of Owned Fund to be submitted as on date of the latest audited balance sheet.

ANNEXURE I

8. 'Sponsor' as defined in terms of Section 2(1) (zh) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.
9. "control" includes the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person, directly or indirectly, including by virtue of his shareholding or management rights or shareholders' agreements or voting agreements or in any other manner.

10. In case the company has changed its name earlier, a list of all the earlier names of the company and date/s of change together with the names of Chief Executive Officer and Chairman at the time of change of name should be furnished.

ANNEXURE II

11. The particulars/information to be furnished in Annexure-II of the application should be based on figures as disclosed in the latest audited balance sheet. However, in the case of a company incorporated on or after 21.6.2002, such particulars/information should be based on the balance sheet as on a date falling within not more than thirty days preceding the date of application.
12. 'Free reserve' includes reserves shown in the balance sheet and created through an allocation out of profits but not being (a) a reserve created for repayment of any future liability or for depreciation on assets or for bad debts, or (b) a reserve created by revaluation of assets of the company.
13. "Related Party" means related parties as per the accounting standards and guidance notes of issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
14. Under / Short provisioning in value of investments, against NPAs and over-recognition of income will be as identified by statutory auditors/internal auditors/RBI inspecting officer.
15. The contents of Annexure II should be certified by a Chartered Accountant.

ANNEXURE III

16. The information about the sponsor, chairman, managing director, directors and the chief executive officer of the company must be certified by each individual, chairman, managing director, directors and the chief executive officer of the company and counter signed by the Authorised Official of the applicant company.
17. Separate form should be submitted in this format of each of such functionaries.

ANNEXURE IV

18. Separate form should be submitted in respect of each of the sponsors.

ANNEXURE V

19. Separate form should be submitted in respect of each of the related party.
 20. The particulars/information should be based on figures as on date of last audited balance sheet as given in Annexure II.
-

**Reserve Bank of India
Department of Non-Banking Supervision
Central Office
World Trade Centre, Centre 1
Cuffe Parade, Colaba
Mumbai**

No.DNBS.2/CGM(CSM)-2003, dated April 23, 2003

**The Securitisation Companies and Reconstruction
Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003**

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Reserve Bank to regulate the financial system to the advantage of the country and to prevent the affairs of any Securitisation Company or Reconstruction Company from being conducted in a manner detrimental to the interest of investors or in any manner prejudicial to the interest of such Securitisation Company or Reconstruction Company, it is necessary to issue the guidelines and directions relating to registration, measures of asset reconstruction, functions of the company, prudential norms, acquisition of financial assets and matters related thereto, as set out below hereby, in exercise of the powers conferred by Sections 3, 9, 10 and 12 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, issues to every Securitisation Company or Reconstruction Company, the guidelines and directions hereinafter specified.

Short title and commencement

1. (1) These guidelines and directions shall be known as 'The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003'.

(2) They shall come into force with effect from April 23, 2003 and any reference in these guidelines and directions to the date of commencement thereof shall be deemed to be a reference to that date.

Applicability of the Directions

2. The provisions of these guidelines and directions shall apply to Securitisation Companies or Reconstruction Companies registered with the Reserve Bank of India under Section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, However, in respect of the trust/s mentioned in paragraphs 8 herein, the provisions of paragraphs 4, 5, 6, 9, 10(i), 10(iii) 12, 13, 14 and 15 shall not be applicable.

3. Definitions

- (1) (i) "Act" means the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002;
- (ii) "Bank" means the Reserve Bank of India constituted under Section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934;
- (iii) "Date of acquisition" means the date on which the ownership of financial assets has been acquired by Securitisation Company or Reconstruction Company;
- (iv) "Deposit" means deposit as defined in the Companies (Acceptance of Deposits) Rules 1975 framed under Section 58 A of the Companies Act, 1956;
- (v) Fair value means the mean of the earning value and the break up value;
- (vi) "Non-performing Asset" (NPA) means an asset in respect of which:
- a) Interest or principal (or instalment thereof) is overdue for a period of 180 days or more from the date of acquisition or the due date as per contract between the borrower and the originator, whichever is later;
 - b) interest or principal (or instalment thereof) is overdue for a period of 180 days or more from the date fixed for receipt thereof in the plan formulated for realisation of the assets referred to in paragraph 7(1)(6) herein;

- c) interest or principal (or instalment thereof) is overdue on expiry of the planning period, where no plan is formulated for realisation of the assets referred to in paragraph 7(1)(6) herein; or
- d) any other receivable, if it is overdue for a period of 180 days or more in the books of the Securitisation Company or Reconstruction Company.

Provided that the Board of Directors of a Securitisation Company or Reconstruction Company may, on default by the borrower, classify an asset as a non-performing asset even earlier than the period mentioned above (for facilitating enforcement as provided for in Section 13 of the Act).

(vii) "Overdue" means an amount which remains unpaid beyond the due date;

(viii) "Owned Fund" means the aggregate of paid up equity capital, paid up preference capital to the extent it is compulsorily convertible into equity capital, free reserves (excluding revaluation reserve), credit balance in Profit and Loss Account as reduced by the debit balance on the profit and loss account and Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted), book value of intangible assets and under / short provision against NPA / diminution in value of investments, and over recognition of income, if any; and further reduced by the book value of the shares acquired in a Securitisation Company or Reconstruction Company, and other deductions required on account of the items qualified by the auditors in their report on the financial statements ;

(ix) "Planning period" means a period not exceeding twelve months allowed for formulating a plan for realization of non-performing assets (in the books of the originator) acquired for the purpose of reconstruction;

(x) "Standard asset" means an asset, which is not an NPA.

(xi) "Trust" means trust as defined in Section 3 of the Indian Trusts Act, 1882.

(2) Words or expressions used but not defined herein and defined in the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, shall have the same meaning as assigned to them in that Act. Any other words or expressions not defined in that Act shall have the same meaning as assigned to them in the Companies Act, 1956.

4. Registration and matters incidental thereto

- (i) Every Securitisation Company or Reconstruction Company shall apply for registration in the form of application specified vide Notification No.DNBS.1/CGM(CSM)-2003, dated March 7, 2003 and obtain a certificate of registration from the Bank as provided under Section 3 of the Act;
- (ii) A Securitisation Company or Reconstruction Company, which has obtained a certificate of registration issued by the Bank under Section 3 of the Act, can undertake both securitisation and asset reconstruction activities;
- (ii) Any entity not registered with the Bank under Section 3 of the Act may conduct the business of securitisation or asset reconstruction outside the purview of the Act.

5. Owned Fund

Every Securitisation Company or Reconstruction Company seeking the Bank's registration under Section 3 of the Act, shall have a minimum Owned Fund of Rs. 2 crore.

6. Permissible Business

- (i) A Securitisation Company or Reconstruction Company shall commence/undertake only the securitisation and asset reconstruction activities and the functions provided for in Section 10 of the Act.
- (ii) A Securitisation Company or Reconstruction Company, which is carrying on any other business, shall cease to do such business by June 20, 2003;

- (iii) A Securitisation Company or Reconstruction Company shall not raise monies by way of deposit.

7. Asset Reconstruction

(1) Acquisition of Financial Assets

- (i) Every Securitisation Company or Reconstruction Company shall frame with the approval of its Board of Directors, a 'Financial Asset Acquisition Policy', within 90 days of grant of Certificate of Registration, which shall clearly lay down the policies and guidelines covering, inter alia,
 - (a) norms and procedure for acquisition,
 - (b) types and the desirable profile of the assets;
 - (c) valuation procedure ensuring that the assets acquired have realisable value which is capable of being reasonably estimated and independently valued;
 - (d) in the case of financial assets acquired for asset reconstruction, the broad parameters for formulation of plans for their realisation.
- (ii) The Board of Directors may delegate powers to a committee comprising any director and/or any functionaries of the company for taking decisions on proposals for acquisition of financial assets;
- (iii) Deviation from the policy should be made only with the approval of the Board of Directors.

(2) Change or take Over of Management/ Sale or Lease of Business of the Borrower

No Securitisation Company or Reconstruction Company shall take the measures specified in Sections 9(a) and (b) of the Act, until the Bank issues necessary guidelines in this behalf.

(3) Rescheduling of Debts

- (i) Every Securitisation Company or Reconstruction Company shall frame a policy, duly approved by the Board of Directors, laying down the broad parameters for rescheduling of debts due from borrowers;

- (ii) All proposals should be in line with and supported by an acceptable business plan, projected earnings and cash flows of the borrower;
- (iii) The proposals should not materially affect the asset liability management of the Securitisation Company or Reconstruction Company or the commitments given to investors;
- (iv) The Board of Directors may delegate powers to a committee comprising any director and/or any functionaries of the company for taking decisions on proposals for reschedulement of debts;
- (v) Deviation from the policy should be made only with the approval of the Board of Directors.

(4) Enforcement of Security Interest

While taking recourse to the sale of secured assets in terms of Section 13(4) of the Act, a Securitisation Company or Reconstruction Company may itself acquire the secured assets, either for its own use or for resale, only if the sale is conducted through a public auction.

(5) Settlement of dues payable by the borrower

- (i) Every Securitisation Company or Reconstruction Company shall frame a policy duly approved by the Board of Directors laying down the broad parameters for settlement of debts due from borrowers;
- (ii) The policy may, interalia, cover aspects such as cut-off date, formula for computation of realisable amount and settlement of account, payment terms and conditions, and borrower's capability to pay the amount settled;
- (iii) Where the settlement does not envisage payment of the entire amount agreed upon in one instalment, the proposals should be in line with and supported by an acceptable business plan, projected earnings and cash flows of the borrower;
- (iv) The proposal should not materially affect the asset liability management of the Securitisation Company or Reconstruction Company or the commitments given to investors;

- (v) The Board of Directors may delegate powers to a committee comprising any director and/or any functionaries of the company for taking decisions on proposals for settlement of dues;
- (vi) Deviation from the policy should be made only with the approval of the Board of Directors.

(6) Plan for realisation

- (i) Every Securitisation Company or Reconstruction Company may, within the planning period, formulate a plan for realisation of assets, which may provide for one or more of the following measures:
 - (a) Rescheduling of payment of debts payable by the borrower;
 - (b) Enforcement of security interest in accordance with the provisions of the Act;
 - (c) Settlement of dues payable by the borrower;
 - (d) Change or take over of the management, or sale or lease of the whole or part of business of borrower after formulation of necessary guidelines in this behalf by the Bank as stated in paragraph 7(2) herein above.
- (ii) The plan for realisation shall clearly spell out the steps proposed to reconstruct the assets and realise the same within a specified timeframe, which shall not in any case exceed five years from the date of acquisition.

8. Securitisation

(1) Issue of Security Receipts

A Securitisation Company or Reconstruction Company shall give effect to the provisions of Sections 7(1) and (2) of the Act through one or more trusts set up exclusively for the purpose. The Securitisation Company or Reconstruction Company shall transfer the assets to the said trusts at the price at which those were acquired from the originator ;

- (i) The trusts shall issue Security Receipts only to qualified institutional buyers; and hold and administer the financial assets for the benefit of the qualified institutional buyers;
 - (ii) The trusteeship of such trusts shall vest with the Securitisation Company or Reconstruction Company;
 - (iii) A Securitisation Company or Reconstruction Company proposing to issue Security Receipts, shall, prior to such an issue, formulate a policy, duly approved by the Board of Directors, providing for issue of security receipts under each scheme formulated by the trust ;
 - (iv) The policy referred to in sub-paragraph (iv) above shall provide that the security receipts issued would be transferable/assignable only in favour of other qualified institutional buyers.
- (2) Disclosures

Every Securitisation Company or Reconstruction Company intending to issue Security Receipts shall make disclosures as mentioned in the annexure.

9. Requirement as to capital adequacy

(1) Every Securitisation Company or Reconstruction Company shall maintain, on an ongoing basis, a capital adequacy ratio, which shall not be less than fifteen percent of its total risk weighted assets. The risk-weighted assets shall be calculated as the weighted aggregate of on balance sheet and off balance sheet items as detailed hereunder:

Weighted risk assets

<u>On-Balance Sheet items</u>	<u>Percentage risk weight</u>
(a) Cash and deposits with scheduled commercial banks	0
(b) Investments in Government securities	0
(c) Other assets	100

Off- Balance Sheet Items

All Contingent Liabilities

50

- (2) Shares held in other Securitisation Companies or Reconstruction Companies shall not attract any risk weight.

10. Deployment of Funds

- (i) A Securitisation Company or Reconstruction Company, may as a sponsor and for the purpose of establishing a joint venture, invest in the equity share capital of a Securitisation Company or Reconstruction Company formed for the purpose of asset reconstruction;
- (ii) A Securitisation Company or Reconstruction Company may deploy any surplus available with it only in Government securities and deposits with scheduled commercial banks in terms of a policy framed in this regard by its Board of Directors;
- (iii) No Securitisation Company or Reconstruction Company shall invest out of its owned fund in land and building, provided that this restriction will not apply to funds borrowed as also to owned fund in excess of the minimum prescribed.

11. Accounting Year

Every Securitisation Company or Reconstruction Company shall prepare its balance sheet and profit and loss account as on March 31 every year.

12. Asset Classification**(1) Classification**

- (i) Every Securitisation Company or Reconstruction Company shall, after taking into account the degree of well-defined credit weaknesses and

extent of dependence on collateral security for realisation, classify the assets into the following categories, namely:

- (a) Standard assets
- (b) Non-Performing Assets.

(ii) The Non-Performing Assets shall be classified further as

- (a) 'Sub-standard asset' for a period not exceeding twelve months from the date it was classified as non-performing asset;
- (b) 'Doubtful asset' if the asset remains a substandard asset for a period exceeding twelve months;
- (c) 'Loss asset' if the asset is non-performing for a period exceeding 36 months or if the asset is adversely affected by a potential threat of non-recoverability due to either erosion in the value of security or non-availability of security or if it has been identified as loss asset by the Securitisation Company or Reconstruction Company or its internal or external auditor.

(iii) Assets acquired by the Securitisation Company or Reconstruction Company for the purpose of asset reconstruction may be treated as standard assets during the planning period, if any.

(2) Asset Reconstruction : Renegotiated / Rescheduled assets

- (i) Where the terms of agreement regarding interest and /or principal relating to standard asset have been renegotiated or rescheduled by a Securitisation Company or Reconstruction Company (other wise than during planning period) the asset concerned shall be classified as substandard asset with effect from the date of renegotiation / reschedulement or continue to remain as a doubtful asset as the case be.
- (ii) The asset may be upgraded as a standard asset only after satisfactory performance for a period of twelve months as per the renegotiated / rescheduled terms.

(3) Provisioning requirements

Every Securitisation Company or Reconstruction Company shall make provision against Non Performing Assets, as under: -

<u>Asset Category</u>	<u>Provision Required</u>
Substandard Assets	A general provision of 10% of the outstanding;
Doubtful Assets	(i) 100% provision to the extent the asset is not covered by the estimated realisable value of security; (ii) In addition to item (i) above, 50% of the remaining outstanding.
Loss Assets	The entire asset shall be written off. (If, for any reason, the asset is retained in the books, 100% thereof shall be provided for).

13. Investments

All investments should be valued at lower of cost or realisable value. Where market rates are available, the market value would be presumed to be the realisable value and in cases where market rates are not available, the realisable value should be the fair value. However, investments in other registered Securitisation Company or Reconstruction Company shall be treated as long term investments and valued in accordance with the Accounting Standards and guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

14. Income recognition

- (i) The income recognition shall be based on recognised accounting principles;

- (ii) All the Accounting Standards and Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India shall be followed in so far as they are not inconsistent with the guidelines and directions contained herein;
- (iii) Interest and any other charges in respect of all the NPAs shall be recognised only when they are actually realised. Any such unrealised income recognised by a Securitisation Company or Reconstruction Company before the asset became non-performing and remaining unrealised shall be derecognised.

15. Disclosures in the balance sheet

- (1) Every Securitisation Company or Reconstruction Company shall, in addition to the requirements of schedule VI of the Companies Act, 1956, prepare the following schedules and annex them to its balance sheet:
 - (i) the names and addresses of the banks/financial institutions from whom financial assets were acquired and the value at which such assets were acquired from each such bank/financial institutions;
 - (ii) Dispersion of various financial assets industry-wise and sponsor-wise. (dispersion is to be indicated as a percentage to the total assets);
 - (iii) Details of related parties as per Accounting Standard and guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the amounts due to and from them; and
 - (iv) A statement clearly charting therein the migration of financial assets from standard to non-performing.
- (2)
 - (i) The accounting policies adopted in preparation and presentation of the financial statements shall be in conformity with the applicable prudential norms prescribed by the Bank.
 - (ii) Where any of the accounting policies is not in conformity with these directions, the particulars of departures shall be disclosed together with the reasons therefor and the financial impact on account thereof. Where

such an effect is not ascertainable, the fact shall be so disclosed citing the reasons therefore.

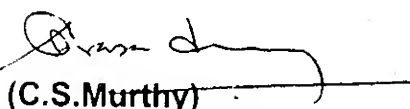
- (iii) An inappropriate treatment of an item in Balance Sheet or Profit and Loss Account cannot be deemed to have been rectified either by disclosure of accounting policies used or by disclosure in notes to balance sheet and profit and loss account.

16. Internal Audit

Every Securitisation Company or Reconstruction Company shall put in place an effective Internal Control System providing for periodical checks and review of the asset acquisition procedures and asset reconstruction measures followed by the company and matters related thereto.

17. Exemptions

The Bank may, if it considers it necessary for avoiding any hardship to Securitisation Company or Reconstruction Company, or for any other just and sufficient reason exempt all Securitisation Companies or Reconstruction Companies or a particular Securitisation Company or Reconstruction Company or class of Securitisation Companies or Reconstruction Companies, from all or any of the provisions of these guidelines and directions either generally or for any specified period, subject to such conditions as the Bank may impose.



(C.S. Murthy)
Chief General Manager-in-Charge

Annexure**(1) Disclosure in Offer Document****A Relating to the Issuer of Security Receipts**

- i. Name, place of Registered Office, date of incorporation, date of commencement of business of the Securitisation Company or Reconstruction Company;
- ii. Particulars of sponsors, shareholders, and a brief profile of the Directors on the Board of the Securitisation Company or Reconstruction Company with their qualifications and experience;
- iii. Summary of financial information of the company for the last three years or since commencement of business of the company, whichever is shorter;
- iv. Details of Securitisation / Asset Reconstruction activities handled, if any, in the last three years or since commencement of business, whichever is shorter.

B Terms of Offer

- i. Objects of offer;
- ii. Description of the instrument giving particulars relating to its form, denomination, issue price, etc together with an averment that the transferability of security receipts is restricted to the qualified institutional buyers ;
- iii. Arrangements made for management of assets and extent of management fee charged by Securitisation Company or Reconstruction Company;
- iv. Interest rate / probable yield;
- v. Terms of payment of principal / interest, date of maturity / redemption;
- vi. Servicing and administration arrangement ;
- vii. Details of credit rating, if any, and a summary of the rationale for the rating;
- viii. Description of assets being securitised,

- ix. Geographical distribution of asset pool;
- x. Residual maturity, interest rates, outstanding principal of the asset pool;
- xi. Nature and value of underlying security, expected cash flows, their quantum and timing, credit enhancement measures;
- xii. Policy for acquisition of assets and valuation methodology adopted ;
- xiii. Terms of acquisition of assets from banks /financial institutions;
- xiv. Details of performance record with the Originators ;
- xv. Terms of replacement of assets, if any, to the asset pool;
- xvi. Statement of risk factors, particularly relating to future cash flows and steps taken to mitigate the same ;
- xvii. Arrangements, if any, for implementing asset reconstruction measures in case of default
- xviii. Duties of the Trustee;
- xix. Specific asset reconstruction measures, if any, on which approvals will be sought from investors;
- xx. Dispute Redressal Mechanism.

(2) Disclosure on quarterly basis

- i. Defaults, prepayments, losses, if any, during the quarter;
- ii. Change in credit rating, if any;
- iii. Change in profile of the assets by way of accretion to or realisation of assets from the existing pool;
- iv. Collection summary for the current and previous quarter;
- v. Any other material information, which has a bearing on the earning prospects affecting the qualified institutional buyers;

STATE BANK OF INDORE
HEAD OFFICE : INDORE

INDORE

DATE : 28.4.2003

NOTICE is hereby given that for the purpose of ascertaining the names of the shareholders of Bank to whom the dividend on their holdings for the year 2002-2003 may become payable, if declared by the Board, the Register of shareholders of the State Bank of Indore will remain closed for transfer of shares From 10-6-2003 to 19-6-2003 (both days inclusive).

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS.


(S. Prasada Rao)
MANAGING DIRECTOR